Institute of Chinese Studies
ICS Analysis
中国研究所 DELHI
No. 34 September 2015

नरेंद्र मोदी के पहले साल में भारत की चीन-नीति का आँकलन*

अलका आचार्य
निर्देशक, चीन अध्ययन संस्थान, दिल्ली
alka.acharya@gmail.com

चीनी जनवादी गणराज्य भारत का केवल अति महत्वपूर्ण पड़ोसी ही नहीं, बल्कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी है, जहाँ का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पीपीपी शर्तों के अनुसार, लगभग दस ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है (जबकि भारत का लगभग दो ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है)। इसका प्रति व्यक्ति जीडीपी भारत से लगभग 6 गुना अधिक है। यही नहीं, साल 2012 से चीन विश्व का तीसरा सबसे बड़ा निवेशक बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर होने वाली संगोष्ठियों में भले ही इन दोनों एशियाई दिग्गजों के बारे में कहा जाता हो कि यह 21वीं शताब्दी को परिभाषित करने वाली शक्तियां है लेकिन हम अगर उनकी क्षमताओं और उपलब्धियों और उन्हें एक-दूसरे से अलग करने वाली व्यापक चौड़ी खाई को ध्यान में रखते हुए उनके समग्र प्रोफाइल को क़रीब से देखें, तो हमें एक विषम चित्र ही दिखाई देता है। इसके अलावा चीन का सैन्य ख़र्च जहाँ उसके जीडीपी का 4.3% है, वहीं भारत में यह 2.5% है, हालांकि इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि चीन का स्वदेशी रक्षा उद्योग भारत के मुकाबले बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया में अनेकानेक हितों के साथ, एक महत्वपूर्ण और बढ़ती शक्ति के रूप में चीनी जनवादी गणराज्य की उपस्थिति बहुत बड़े स्तर पर है। एशिया में इसकी आर्थिक और राजनितिक-सामरिक उपस्थिति, खासकर भारत के निकटतम पड़ोस में, भारतीय नीति

निर्माताओं के लिए अब मुख्य सामरिक चिंता बन चुकी है। ये दो पहलू - एक तरफ़ दोनों के बीच भारी विषमता और दूसरी तरफ़ भारत के आस-पड़ोस में एजेंडा-सेटर के तौर पर चीन की बढ़ती हुई क्षमता - एशिया में जहाँ समग्र परिवेश को तय करने वाले कारक बन चुके हैं, वहीं भारतीय विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी।

भारत के आस-पड़ोस में एजेंडा-सेटर के तौर पर चीन की बढ़ती हुई क्षमता एक चिंताजनक विषय बन चुकी है।

दूसरी तरफ़, जैसा हम जानते हैं, भारत-चीन संबंध पिछले दो दशकों से लगातार सामान्य होने की ओर अग्रसर हैं और इनमें कई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भी हुए हैं। 1980 के दशक के अंत से ही नीति से संबंधित ढांचा काफ़ी स्थिर रहा है। इस दौरान आपसी रिश्तों का दायरा निरंतर बढ़ता ही रहा है और आज के संदर्भ में, भारत-चीन संबंधों का स्वरुप बहुत व्यापक और विस्तृत हो चुका है। सीमा को लेकर दोनों तरफ़ से जो दावे किये जाते हैं, वही केवल इस रिश्ते को परिभाषित नहीं करते - दोनों देशों ने अपने मतभेदों को इसमें आड़े नहीं आने दिया है। लेकिन, इसका यह मतलब नहीं है कि वहां अब कोई झड़प नहीं होती। दोनों देशों के बीच सीमा को लेकर विवाद अब भी बना हुआ है, इसका पता हमें सामरिक/सुरक्षा से संबंधित लेखों से चलता है, जो यह बताते हैं कि भय अब भी कहीं न कहीं बना हुआ है । इसके बावजूद, दोनों देशों के बीच तनाव और अनिश्चितता के स्तर में सराहनीय कमी आई है। द्विपक्षीय विवादास्पद मुद्दों के निपटारे के लिए, मध्यस्थ तंत्र और दोनों सरकारों के बीच संवाद में तेज़ी आई है। सबसे बड़ी बात यह कि द्विपक्षीय व्यापार में बड़ा उछाल आया है, जो कि 2011 में 73 बिलियन अमरीकी डॉलर के बराबर रहा। अनुमान यह लगाया जा रहा है कि 2017 में यह 100 बिलियन तक पहुँच जाएगा।

आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते भारत-चीन संबंध के सबसे गतिशील, तेज़ी के साथ बदलते हुए और परिवर्तनकारी पहलू को दर्शाते हैं, हालाँकि इसकी वजह से कुछ ज़रूरी (और कुछ ग़लत) चिंताएं पैदा हो रही हैं। चीन की बेहतर निर्माण शक्ति और औद्योगिक क्षमता ने व्यापार घाटे को चीन के हक़ में कर दिया है, जो कि लगभग 35 बिलियन अमरीकी डॉलर है और जिसके बारे में भारत में ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थिति है, जिससे केवल चीन का ही फ़ायदा होगा।[1] इस संदर्भ में हमें यह बात ध्यान में रखना चाहिए कि आज के दौर में, भारत की औद्योगिक क्षमताएं पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं जिस वजह से, व्यापार का यह स्वरुप एक तरह से स्वाभाविक है।

---

1 वर्ष 2011 से ही लगभग 10% की गिरावट देखने को मिलती रही है, जिसकी वजह से 2013-14 में यह स्तर 66.57 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुँच गया। यह गिरावट अधिकतर इस वजह से रही कि भारत ने अपने निर्यात से तीन गुना अधिक आयात किया और निवेश कम रहा। यहाँ तक कि वर्ष 2012 में भी भारत के व्यावसायिक केंद्र, मुंबई से बीजिंग या शंघाई के बीच कोई सीधी उड़ान (डायरेक्ट फ्लाइट) नहीं थी।

भारत में केन्द्र में जो भी सरकार रही है, सर्वोच्च स्तर पर एक राजनीतिक संकल्प हमेशा क़ायम रहा है, जो कि प्रतिस्पर्धी पहलुओं को दुरुस्त करने, साझा चिंता और हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर समन्वय को बढ़ाने और एक "सामरिक और सहयोगी साझेदारी" के निर्माण के लिए निरंतर प्रतिबद्ध रहा है।

सीमा विवाद और परस्पर सहमति वाली वास्तविक नियंत्रण रेखा की अनुपस्थिति के बावजूद, जहाँ समय-समय पर सीमा उल्लंघन की वारदातें होती रहती हैं, दोनों देश यह भली-भांति समझते हैं कि सैन्य शक्ति के माध्यम से, वे एक-दूसरे पर कोई हल थोप नहीं सकते। मई 2014 में जब नई सरकार ने अपना पदभार संभाला, उसके कुछ पहले और बाद भारत-चीन सीमा पर दो बड़ी घटनाएं हुईं और उसी दौरान चीन की तरफ़ से भारत के दो उच्च-स्तरीय दौरे भी हुए। पहला दौरा प्रधानमंत्री ली ख:छियांग ने मई 2013 में किया, जबकि दूसरा दौरा चीनी राष्ट्रपति शी चिंपिंग द्वारा सितंबर 2014 में किया गया। कुल मिलाकर अगर देखा जाये, तो भारत-चीन संबंध संतुलित रहे हैं, स्थिति को संभाला गया। विवादित सीमा को भारत की कमज़ोरी बनाने की कोशिश की जा सकती है, परंतु दोनों पक्ष इस मसले को बातचीत के द्वारा हल करने के पथ पर अग्रसर हैं और मेरा मानना है कि, इस बात की संभावना बहुत कम है कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए कोई भी देश ताक़त का इस्तेमाल करेगा।

एनडीए-II का प्रारंभ: कुछ निरंतरता और कुछ परिवर्तन

साल 2014 के आम चुनाव के दौरान, घरेलू आर्थिक सुधार और विकास का एजेंडा, भाजपा के प्रचार अभियान पर छाया रहा। उस प्रचार अभियान में कुछेक यादगार, लेकिन विवादास्पद अपवादों को छोड़ कर, विदेश नीति से संबंधित मुद्दे या चुनौतियों, या फिर ख़ास कर अपने देश से जुड़ी चिंताओं की अभिव्यक्ति देखने को नहीं मिली।

दोनों देशों के बीच तनाव और अनिश्चितता के स्तर में सराहनीय कमी आई है।

प्रथम, अक्टूबर 2013 में 'भारत और दुनिया' के विषय पर दिए गए अपने एक व्याख्यान में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ने तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर इशारा किया: पहला यह कि "विदेश नीति के मामलों में हम चीन को भारत पर हावी नहीं होने दे सकते"; दूसरा यह कि "अब समय आ गया है कि हम राजनीतिज्ञों द्वारा नहीं, बल्कि जनता के द्वारा संचालित विदेश नीति को अपनाएं"; और तीसरा, "अब समय आ गया है कि विदेश नीति के संचालन में हम अपनी सांस्कृतिक शक्तियों का प्रयोग करें।" (*Press Trust of India* 2013) द्वितीय, फ़रवरी 2014 में अरुणाचल प्रदेश (जिस पर चीन अपना हक़

जताता है) में एक चुनावी रैली में मोदी ने काफ़ी उत्तेजित होते हुए चीन को यह चेतावनी दे डाली थी कि "वह अपनी विस्तारवादी सोच को विराम दे।" आगे यह भी कहा कि "अरुणाचल प्रदेश हमारा है और दुनिया की कोई भी शक्ति इसे हमसे छीन नहीं सकती।" (*Press Trust of India* 2013)

पुराने ढांचे पर रिश्तों को आगे बढ़ाते हुए, कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन भी देखने को मिले हैं।

बतौर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, मोदी जी का चुनावी रुख़ हमें हर विपक्षी पार्टी द्वारा चीन और पाकिस्तान को लेकर अपनाए गए मज़बूत राष्ट्रवादी तेवर का स्मरण कराता है। इन वक्तव्यों ने कुछ अंध-राष्ट्रवादी भावनाओं को तो जन्म दिया, लेकिन अधिकतर लोगों को इससे हैरानी नहीं हुई। कुछ ऐसी भी टिप्पणियां आयीं, जिनमें कहा गया कि भाजपा-नेतृत्व वाली सरकार सीमा-विवाद पर चीन के ख़िलाफ़ कड़ा रुख़ अपनाएगी।

बहरहाल, अधिकतर लोगों की सोच यही थी कि एनडीए-II के अंतर्गत भारतीय विदेश-नीति आर्थिक विकास और आधुनीकरण के घरेलू एजेंडे से प्रेरित रहेगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के पहले वर्ष में यह देखने को भी मिला है - इस पहले वर्ष में अपने सभी 16 देशों के दौरे में उन्होंने स्पष्ट तौर पर यही संदेश दिया है कि भारत के दरवाज़े विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी और निवेश के लिए पूरी तरह खुले हुए हैं। मोदी सरकार की स्थापना के बाद, यह स्पष्ट किया गया कि भारत अपने दक्षिण-एशियाई पड़ोसियों को प्राथमिकता देगा। प्रधानमंत्री मोदी के पहले विदेश दौरे अपने पड़ोसी मुल्कों के थे - सीधा संदेश यही था कि भारत सरकार क्षेत्रीय संबंधों को एक नया आयाम देना चाहती है और साथ ही दक्षिण-एशिया में आर्थिक परिवर्तन के चालक के तौर पर उभरने की नींव डालना चाहती है। पड़ोसियों के साथ स्थिर संबंध और सक्रिय विदेश-नीति भारत के ख़ुद अपने उत्थान का आधार बनेगी।

दिलचस्प बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चीन के साथ संबंध के पीछे एक इतिहास है। गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी शायद राज्य स्तर के ऐसे पहले नेता थे, जिन्होंने अपने यहाँ चीनी निवेश और व्यापार को आमंत्रित करने में पूरी सक्रियता दिखाई। उन्होंने चीन का दौरा तीन बार किया - पहला 2006 में, दूसरा 2007 में और तीसरा 2011 में - (बीच-बीच में उन्होंने सिंगापुर और जापान के भी दौरे किये)। इन दौरों के बाद उन्हें यक़ीन हो गया कि भारत के विकास और आधुनिकरण में चीन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दूसरी तरफ़, उस समय चीन के विश्वास में भी बढ़ोतरी हुई, क्योंकि मोदी की निगरानी में गुजरात के अंदर निवेश करने का चीन का व्यावसायिक अनुभव काफ़ी संतोषजनक रहा।

प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के द्वारा चीन का पहला दौरा, जो कि उनके प्रधानमंत्रित्व-काल के पहले वर्ष का अंत भी था, उनके पुराने संबंधों को बरक़रार रखने में काफ़ी सहायक तो साबित हुआ

ही, इसमें कुछ उल्लेखनीय परिवर्तन भी देखने को मिला। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि चीन के साथ नए सिरे से संबंध बनाने की ज़रुरत पेश नहीं आई, बल्कि नई सरकार ने उसी ढांचे पर रिश्तों को आगे बढ़ाना शुरू किया, जो 1980 के दशक के आख़िरी दिनों से अपनी जगह पर बना हुआ है, और वह यह है कि मतभेदों को अलग रखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाया जाये और उन क्षेत्रों का विस्तार किया जाये, जहाँ आपस में समानता हो। लेकिन, इसके अलावा भी कुछ नए तत्व हैं, क्योंकि मोदी इन संबंधों में एक नई शक्ति फूंकने और उसमें तीव्रता पैदा करने में कामयाब हुए हैं।

मोदी के चीन दौरे के समय राष्ट्रपति शी चिंपिंग ने एक अनोखा क़दम उठाते हुए, पेइचिंग से बाहर निकल कर शियान में मोदी के साथ एक दिन बिताया। यह बात पूरे चीनी मीडिया में छाई रही और इसकी जमकर तारीफ़ हुई। शियान में जिस प्रकार का महत्त्व सांस्कृतिक और धार्मिक परिवेश को दिया गया, उसी पर मोदी सरकार का रुझान साफ़-साफ़ दिख रहा है। भारत-चीन ऐतिहासिक-सांस्कृतिक कड़ियों का ज़िक्र हालाँकि दोनों तरफ़ से दौरा करने वाले नेताओं के सभी भाषणों में सदैव होता रहा है, फिर भी मोदी ने ऐतिहासिक सांस्कृतिक और सभ्यतागत आयाम को इस प्रकार पेश किया है कि आर्थिक और राजनितिक-सामरिक स्तंभों जैसा ही यह भी एक प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं। अगर इसे योजनाबद्ध तरीक़े और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया गया, तो यह दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों को मज़बूत करने में काफ़ी हद तक सहायक हो सकता है।

एक लंबे समय के बाद हमने किसी भारतीय नेता को चीन की धरती पर सीमा-विवाद के बारे में इतना खुल कर बोलते हुए देखा, जैसे उनका यह बयान कि चीन को अपने कुछ रुख़ों पर फिर से सोचना चाहिए और इस विवाद को सामरिक और दीर्घ-कालिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। लेकिन साथ ही उन्होंने चलते रहने, और आगे बढ़ते रहने की भी बात की। यह पूरी तरह स्पष्ट था कि बीजिंग में उन्होंने जो कुछ कहा, उसे चीन और भारत के बाहर भी सुना गया - इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे एशिया में अधिकतर लोगों ने नई सरकार के द्वारा भारत-चीन सहयोग की निरंतर प्रतिबद्धता के संदेश को सुनकर राहत महसूस की होगी। (Ministry of External Affairs, Government of India 2015)

सांस्कृतिक और सभ्यतागत पहलू भी आर्थिक और राजनितिक-सामरिक स्तंभों जैसे ही एक प्रमुख स्तंभ बन सकते हैं।

निवेश और व्यापार पर भी ख़ासा ज़ोर दिया गया - और अगर इसकी शुरुआत होती है, तो पूरे एशिया में यह प्रमुख आर्थिक साझेदारी होगी। प्रधानमंत्री ने चीन के सामने 'ब्रांड इंडिया' को सबसे आगे रखा। लेकिन, यह तो आसान काम था। अभी 20 बिलियन डॉलर का सवाल यही है कि भारत में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक घरेलू और दूसरे ढांचागत सुधार (ख़ास कर भूमि-अधिग्रहण) कब (और

कितनी जल्द) होंगे - क्योंकि तभी भारत-चीन आर्थिक संबंध, पारस्परिक लाभ और संवर्धन के अपने लंबे सफ़र को शुरू कर सकते हैं।

एक और दिलचस्प बात यह है कि मोदी ने अपनी सरकार के पहले वर्ष में, विदेश दौरों की कड़ी में चीन को अपना आख़िरी पड़ाव बनाया। शायद वह यह देखना चाहते थे कि विश्व-शक्ति के दूसरे प्रमुख केन्द्रों पर उन्हें जो प्रतिक्रिया मिली, और उन दौरों के जो परिणाम निकल कर आये, विभिन्न मुद्दों पर चीन जिस प्रकार का रुख़ अपनाता रहा है, इस पर उसका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं। शायद वह अब भी चीन के प्रति अपने नज़रिये को दुरुस्त करना चाहते थे, इस बात को भलीभांति जानते हुए कि सितंबर 2014 में राष्ट्रपति शी चिंपिंग के भारत दौरे के समय दुर्भाग्यपूर्ण "आक्रमण" की जो घटना घटी थी, उसने ज़्यादातर भारतीयों पर नकारात्मक प्रभाव डाला था।

मौजूदा दौर दोनों के लिए रणनीतिक अवसर का समय है - विकास और आधुनिकरण को प्राथमिकता प्रदान करना दोनों की ज़रूरत है।

भारतीय प्रधानमंत्री इस बात से हरगिज़ बेख़बर नहीं हैं कि चीन के साथ इस अति-विषम संबंध को निभाना चुनौतियों से भरा हुआ है, क्योंकि चीन की आर्थिक ताक़त और सैन्य क्षमता भारत के मुक़ाबले अधिक बेहतर है। इसी विषमता के परिदृश्य में उनको अपनी चीन-नीति को बनाना और आगे बढ़ाना है, यह ध्यान में रखते हुए कि भारत के विकास कार्यों में चीन की भूमिका गेम-चेंजर की हो सकती है। घरेलू सतह पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे, जो बुरा-भला कहेंगे और चीन पर 'नरम रवैया" अपनाने के लिए एनडीए पर हमला करेंगे। अंत में मोदी की सबसे बड़ी चुनौती होगी उस उभरते हुए चीन के प्रति संतुलित और क्रियात्मक रणनीति तैयार करना, जो एशिया में राजनीतिक, आर्थिक और सिक्योरिटी एजेंडा सेट करने की अपनी क्षमता का तेज़ी से प्रदर्शन कर रहा है।

भारतीय प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले साल में नरेंद्र मोदी ने जिन सोलह देशों का दौरा किया, उनमें चीन का दौरा यक़ीनन सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। हम यह भी कह सकते हैं कि तमाम बड़ी शक्तियों के साथ भारत के रिश्तों का स्वरुप कुछ हद तक इस बात पर निर्भर रहेगा कि चीन के साथ भारत के किस तरह के संबंध क़ायम होते हैं। एक तरफ़ जहां बहुत से सामरिक लेखों में भारत को 'स्विंग स्टेट' के रूप में पेश किया जा रहा है, वहीं चीन की बढ़ती हुई ताक़त की आड़ में एशियाई भू-राजनीतिक गतिशीलता के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी दिखाई दे रही है। यह हमें मोदी के जापान, अमरीका और दूसरे पश्चिमी देशों के दौरे के दौरान देखने को मिला। लेकिन, अभी यह देखना बाक़ी है कि सभी बड़ी शक्तियों के साथ अपने संबंधों को बनाये रखने में और आगे बढ़ाने में एनडीए-II कितना निपुण है - ख़ास कर तब, जब चीन, जापान और अमरीका के अंतर्विरोध मुखर होते जा रहे हैं।

समस्याएं और संभावनाएं

सीमा विवाद

चीन और पाकिस्तान की "टिकाऊ" दोस्ती और भारत-चीन सीमा विवाद द्विपक्षीय संबंधों में सबसे बड़ा सर दर्द हैं, भले ही इसको लेकर थोड़ा मतभेद हो सकता है कि दोनों में से कौन सी समस्या ज़्यादा ख़तरनाक है। सीमा-विवाद के साथ, ज़ाहिर है, तिब्बत का भी मामला जुड़ा हुआ है। भारत में दलाई लामा और तिब्बती निर्वासन सरकार की उपस्थिति चीनी असुरक्षा को भड़काती है। हालांकि, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र पर चीनी संप्रभुता को भारत आधिकारक तौर पर मानता है, इसके बावजूद चीनी सुरक्षा प्रतिष्ठान में संदेह का भाव हर जगह पाया जाता है। परिणाम-स्वरुप, भारत-चीन "सामरिक भागीदारी" में दृढ़ विश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में रणनीतिक खाई पूरी तरह स्पष्ट है।

पांच दशकों से चला आ रहा सीमा-विवाद का यह मसला, किस प्रकार सामान्य कार्यवाही में बाधा डालता (ख़ास कर भारत के लिए) और अविश्वास को बढ़ाता है, यह तब देखने को मिला, जब सितंबर 2014 में राष्ट्रपति शी के भारत दौरे के समय चीनी सैनिकों के साथ-साथ वहां के कुछ नागरिक नियंत्रण रेखा (एलओएसी) पार करके लदाख सेक्टर में दाख़िल हो गए। (Rajan 2014) राष्ट्रपति शी चिंपिंग के दौरे के समय घटित यह सीमा उल्लंघन जहाँ एक तरफ़ अनिर्धारित सीमा रेखा की अनिश्चितता और ख़तरों को रेखांकित करता है, दूसरी तरफ़, उन समझौतों की विश्वसनीयता को भी क़ायम करता है, जो ख़ास कर ऐसे हालात को कंट्रोल करने के लिए बनाये गए हैं। इस बात को स्वीकार करते हुए कि बातचीत के ज़रीये झगड़े को शांत करने का मौजूदा तरीक़ा काम आया, यह भी मानना पड़ेगा कि विवाद के लगातार बने रहने और साथ ही मीडिया के द्वारा समय-समय पर मतभेदों को अनावश्यक उछाल देने से जन-धारणा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक दल हमेशा इस खतरे को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करते हैं, जिसके चलते मौजूदा सरकार के द्वारा समाधान निकालने की रफ़्तार कम होने लगती है, क्योंकि यह बात भी अब साफ़ हो चुकी है कि सीमा विवाद का समाधान 'कुछ लेने और कुछ देने' से ही सुलझ सकता है।

> *भारत-चीन "सामरिक भागीदारी" में दृढ़ विश्वास की कमी पाई जाती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में रणनीतिक खाई पूरी तरह स्पष्ट है।*

भारत-चीन-पाकिस्तान त्रिकोण

जहाँ तक चीन और पाकिस्तान के दरमियान संपर्कों का सवाल है, तो इसको लेकर भारत में अत्याधिक शंकाएं पाई जाती हैं। चीनी विद्वानों की राय में, "पिछले वर्षों की एकल-स्तंभ नीति (अर्थात पाकिस्तान) के मुक़ाबले दक्षिण-एशिया के साथ चीन के रिश्ते समानांतर और बहु-स्तंभीय बन चुके हैं।" (Ye 2008) दूसरी तरफ़, पाकिस्तान में होने वाली आतंकी गतिविधियों के

अंतर्राष्ट्रीय असर की वजह से, इसे "अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के केंद्र" (George and Raj 2013) ख़तरों को कम के तौर पर देखा जा रहा है। (Bhattacharya 2014) चीनी वार्ताकारों ने अपने भारतीय समकक्षों के साथ होने वाली बातचीत में अक्सर, पाकिस्तान में बढ़ते हुए धार्मिक आतंकवाद पर चिंता व्यक्त की है।

जहाँ तक पाकिस्तान में मौजूद भारत-विरोधी आतंकी गतिविधियों का सवाल है, तो चीनी हाव-भाव नैतिकता के विरुद्ध दिखाई देते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है।

ऐसा प्रतीत होता है कि इन धार्मिक आतंकवादियों के चलते, जिन्होंने पाकिस्तान में ट्रेनिंग हासिल की है या जिन्हें वहां पनाह मिली हुई है, और जो शिंचियांग में भी सक्रिय होना चाहते हैं, ख़ुद अपनी समस्याओं की वजह से चीनियों ने उन्हें दबाने या ख़त्म करने के लिए पाकिस्तानी अधिकारियों से सहयोग माँगा है, ताकि वह अपने ख़तरों को कम कर सकें। जहाँ तक पाकिस्तान में मौजूद भारत-विरोधी आतंकी गतिविधियों का सवाल है, तो चीनी हाव-भाव नैतिकता के विरुद्ध दिखाई देते हैं, जो कि भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इसके अलावा, पाक-अधिकृत कश्मीर में चीन की ज़मीनी कार्यवाहियां, जहाँ बुनियादी ढांचे में निवेश किया जा रहा है, भारत-नियंत्रित जम्मू-कश्मीर के बारे में चीनी नज़रिये के बिल्कुल उलट हैं। भारत-नियंत्रित जम्मू-कश्मीर के बारे में चीन की तरफ़ से संकीर्ण नज़रिया अपनाया जाता है (कि यह विवादित क्षेत्र है) और इस तथ्य को हल्का किया जाता है कि यह भारतीय प्रशासन के अधीन है। इन वर्षों में चीन-पाकिस्तान संबंधों, जिसमें चीन ने परमाणु हथियार तैयार करने और उपरोक्त सुविधा मुहैया कराने में पाकिस्तान की सहायता की, के स्वरुप और गुणवत्ता के बारे में ख़्याल किया जाता है कि वह पाकिस्तानी संवेदनाओं के अनुरूप ज़्यादा हैं, जो चीन के इस दावे को कमज़ोर करता है कि पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते भारत की क़ीमत पर नहीं हैं। निस्संदेह, हम दक्षिण-एशिया में विशेष कर, लंबे समय तक 'सुरक्षा संबंधी परस्पर निर्भरता' का एक अंश भी तैयार करने से कोसों दूर हैं।

अन्य मसले

पुरानी और लगातार बनी रहने वाली समस्याओं, जैसे सीमा-विवाद और चीन-पाक गठजोड़ के एलावा कुछ नई परेशानियों को भी जोड़ा जा सकता है - मिसाल के तौर पर कश्मीर से चीन का सफ़र करने वालों को नत्थी वीज़ा जारी करना और तिब्बत में यारलुंग त्सांगपो नदी (जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है) के ऊपर बांध बनाकर भारत की जलापूर्ति को बाधित करने का चीन द्वारा कथित प्रयास। इसके बाद वह समस्याएं हैं, जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वह सीज़नल हैं या फिर वो, जो विशिष्ट संदर्भ में पैदा होती हैं और उनके साथ सुरक्षा का भी कोई न कोई पहलू जुड़ा रहता है, जैसा कि हुआवी जैसी चीन की बड़ी टेलीकॉम कंपनियों की भारतीय बाज़ार में प्रस्तावित प्रवेश का मामला। भारत के

उत्तर-पूर्वी राज्यों से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों और हिंद महासागर में चीनी गतिविधियों को जोड़ कर इस लिस्ट को और भी बड़ा किया जा सकता है।

संभावनाएं

इनमें से कुछ समस्याओं की कठोरता और जटिलता के बावजूद ये इशारे तो मिलते ही हैं कि आपसी संबंधों में गति, विविधता और गहराई पैदा हुई है। अधिकतर विश्लेषक और मीडिया अक्सर इस तथ्य को बिल्कुल नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि भारत ने चीन के साथ जितने घोषणापत्रों और आधिकारिक संयुक्त-वक्तव्यों पर दस्तख़त किये हैं, उतने किसी और देश के साथ नहीं। उदहारण के तौर पर हम भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके चीनी समकक्षों के बीच दस वर्षों में हुई 30 मुलाक़ातों को पेश कर सकते हैं, जो कि तेज़ी से मज़बूत होते रिश्तों का प्रमाण हैं। उसी तरह अभी एक साल के अंदर मोदी और शी चिंपिंग के दरमियान पांच बैठकें हो चुकी हैं, जो कि समान रूप से शुभ संकेत हैं। हम भली-भांति यह कह सकते हैं कि 1962 के बाद भारत-चीन रिश्तों का सबसे बेहतर दौर इस वक़्त चल रहा है। ख़ास कर जबसे नई शताब्दी का आरंभ हुआ है, यद्यपि चीन और पाकिस्तान के सामरिक रिश्ते कुछ और गहराए हैं, दक्षिण-एशिया के साथ चीन के संबंधों के संदर्भ में भारत और चीन के रिश्ते को दोबारा केन्द्रीयता प्राप्त होने लगी है।

यह मूल्यांकन इस हाइपोथेसिस (परिकल्पना) पर आधारित है कि मौजूदा दौर दोनों के लिए रणनीतिक अवसर का समय है, क्योंकि विकास और आधुनिकरण के घरेलू एजेंडे को प्राथमिकता प्रदान करना दोनों की ज़रूरत है। भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2014-15 के अनुभाग 'क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल' में द्विपक्षीय समझौते के बारे में कहा गया है कि "सीमा पर अमन और शांति दोतरफ़ा रिश्तों में वृद्धि और निरंतर विकास के लिए बेहद ज़रूरी है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पर गहरी नज़र रखना ज़रूरी है, लेकिन इसमें उसे कहीं भी ख़तरा नहीं बताया गया है।[2]

जबसे नई शताब्दी का आरंभ हुआ है, यद्यपि चीन और पाकिस्तान के सामरिक रिश्ते कुछ और गहराए हैं, दक्षिण-एशिया के साथ चीन के संबंधों के संदर्भ में भारत और चीन के रिश्ते को दोबारा केन्द्रीयता प्राप्त होने लगी है।

शी चिंपिंग द्वारा सितंबर 2014 में भारत का दौरा और मई 2015 में मोदी के द्वारा चीन का दौरा, इन दोनों ने इस बात को रेखांकित किया कि चीन और भारत के "विकास के लक्ष्य एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका क्रियान्वयन परस्पर सहायक तरीक़े से होना चाहिए;" (MEA, GoI 2014) और यह कि विकास प्रक्रियाएं एक-दूसरे को मज़बूत

[2] "India remains conscious and watchful of the implication of China's increasing military profile in our immediate and extended neighbourhood, as well as the development of strategic infrastructure by China in the border areas. India is also taking necessary measures to develop the requisite capabilities to counter any adverse impact on our own security" (Ministry of Defence, Government of India 2015).

करती हैं। इसने एक नए शीर्षक - भारत-चीन "विकासात्मक साझेदारी" - को जन्म दिया है, जो अब सामरिक और सहायक साझेदारी का प्रमुख घटक होगा।" अड़ियल भू-राजनीति या फ़ालतू हिसाब-किताब इस लक्ष्य से केवल हटाने का काम करेंगे, क्योंकि यह आर्थिक संबंधों के दायरे को प्रभावी तरीक़े से सीमित कर देगा।

चीन अजेय नहीं है - उसके सामने बड़ी घरेलू चुनौतियाँ और बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं, जो कि स्थिरता के लिए ख़तरा हैं।

यह स्वागत योग्य ख़बर है कि चीन ने गुजरात और महाराष्ट्र में दो औद्योगिक पार्क बनाने का वादा किया है और साथ ही वह भारत में अगले पांच सालों तक विभिन्न औद्योगिक और ढांचागत परियोजनाओं में 20 बिलियन अमरीकी डॉलर निवेश करने की कोशिश करेगा। इनमें वह चार क्षेत्र भी शामिल हैं, जो भारतीय रेलवे के उन्नयन से जुड़े हुए हैं। आर्थिक और वित्तीय मामलों पर संस्थागत बातचीत, असैनिक परमाणु ऊर्जा का संवर्धन, संस्कृति, युवाओं का आदान-प्रदान, पर्यटन भाषा का शिक्षण तथा प्रांतीय/राज्य संबंधों की स्थापना जैसे दूसरे क्षेत्रों में सहयोग की परिकल्पना भी 2014 के साझा बयान में की गयी है। इससे आने वाले दिनों में, दोनों देशों के व्यापारिक हलक़ों में निहित स्वार्थ पैदा होगा। जैसा कि चीन-अमरीकी आर्थिक संबंधों ने दर्शाया है, इन इंट्रेस्ट समूहों में ऐसे तत्व भी शामिल हैं, जिन्होंने तेज़ी से बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सत्ता के फेर-बदल के दौरान, अपरिहार्य भू-राजनितिक तापमान को कम करने में प्रभावशाली भूमिका निभाई है।

दिशा की खोज

इसमें कोई संदेह नहीं है कि चीन एक विशाल अवसर प्रदान कर रहा है। भारत ऐसे देशों और क्षेत्रों से घिरा हुआ है, जो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। हमें चुनौतियों का सामना करने और संभावनाओं से लाभ उठाने का रास्ता तलाश करना चाहिए, और उम्मीद है कि हम ऐसा कर भी रहे हैं। चीन के संदर्भ में हमारे पास जिस प्रकार के विकल्प हो सकते हैं, वह इस बात पर निर्भर है कि हम चीनी ताक़त की प्रवृत्ति को किस तरह समझते हैं। उभरता हुआ दबंग/आक्रामक चीन, इस मानचित्र और स्वरुप का हमें व्यापक ढंग से विश्लेषण करना चाहिए। अव्वल, जो देश अधूरे या अपूर्ण विकास की चुनौतियों के साथ जूझ रहा है, उस देश की नीतियां मूलरूप से बचाव की मुद्रा में रहती हैं।

दूसरा, चीन अजेय नहीं है - उसके सामने बड़ी घरेलू चुनौतियाँ और बहुत से सामाजिक मुद्दे हैं, जो कि स्थिरता के लिए ख़तरा हैं, चीन में सत्ताधारी वामपंथी दल के लिए सर्वोच्च प्राथमिक कार्य यही है। तीसरा, बेल्ट और रोड की चीन की 'भव्य रणनीति' को सफ़ल बनाने के लिए, इसमें शामिल सभी देशों की सक्रिय भागीदारी की ज़रूरत पड़ेगी - ऐसे में ज़ाहिर है कि वह भारत की ओर से संभावित विरोध को कम करने के तरीक़े ढूंढ रहा होगा। भारत-चीन संबंधों में बेशक प्रतिस्पर्धी और सहकारी, दोनों ही

आयाम हैं। परंतु, यह एक सीमित ढांचा है, जिससे बाहर निकल कर ही हम इस रिश्ते को ऊँचा उठा सकते हैं।

चौथा, चीन और भारत दोनों ही इस बात को स्वीकार करते हैं कि उनके आपसी संबंध एशिया की स्थिरता और पुनरुत्थान के लिए मज़बूत आधार हैं, इसलिए इन संबंधों को बनाए रखना उनकी ज़रूरत है, क्योंकि बंटा हुआ एशिया किसी के लिए भी लाभकारी नहीं होगा। इसके साथ ही, एशिया में वैकल्पिक आर्थिक एवं राजनीतिक संरचनाओं और संस्थाओं के स्थापन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। बहुपक्षीय सुरक्षा व्यवस्थाओं पर भी ग़ौर किया जा रहा है। मौजूदा अलोकतांत्रिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक-आर्थिक ढांचे का पुनःनिर्माण करने की बात चल रही है। भारत को इस नए उभरते हुए चर्चा में भाग लेने की ज़रूरत है - चीन के साथ इन मुद्दों पर सक्रियता के साथ बातचीत को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पांचवां, मोदी सरकार के अंतर्गत, भारत दक्षिण-एशिया में क्षेत्रीय एकता का आर्थिक सूत्रधार बनना चाहता है, जहाँ हम पहले से ही देख रहे हैं कि चीन ने कई जगहों पर विकास परियोजनाओं में अपना सहयोग दिया है।

इन सबके बावजूद, इस बात को भली-भाँति समझता है कि भारत की सक्रिय, सकारात्मक और साझेदार भूमिका के बग़ैर वह दक्षिण-एशिया में अधिक समय तक कामयाब नहीं हो सकता। चीन दक्षिण-एशिया में विकास, उन्नति और आधुनिकरण के अवसर मुहैया कराने में बड़ी भूमिका निभा सकता है, लेकिन ये सब भारत के साथ मिल कर होना चाहिए, केवल व्यावहारिक या कूटनीतिक तौर पर ही नहीं, बल्कि सामरिक तौर पर भी। अंत में, भारत और चीन के बीच बातचीत को अगर हम सार्थक देखना चाहते हैं, तो हमें हर सतह पर और हर तबक़े को जोड़ कर, इसको प्रोत्साहित करना होगा। दोनों मुल्कों के विद्वानों, बुद्धिजीवियों, छात्रों, संस्कृति कर्मियों, उद्यमियों, पेशेवरों और आम नागरिकों के आपसी विचारों और ऊर्जा के आदान-प्रदान के लिए सरकार को पूरी सुविधा प्रदान करनी होगी। आज सारा संसार चीन की तरफ़ रुख़ किये हुए है; अगर हम अपने पड़ोसी को बेहतर समझना चाहते हैं, तो सीधी आपसी बातचीत और विचारों का आदान-प्रदान अत्यावश्यक है। फ़िलहाल इस प्रकार के आवागमन और आदान-प्रदान पर जो अतर्कसंगत रोक है, नई सरकार को उनका नए सिरे से परीक्षण करना होगा।

*Kolkata Society for Asian Studies द्वारा University of Calcutta, Department of Political Science और Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies के सहयोग से 12-13 August 2015 को *New regime under NDA Government and Sino-Indian Relations: Expectation and Uncertainty* शीर्षक पर कोलकाता में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में दिये गए व्याख्यान का अनुवाद।

REFERENCES

Bhatt, Sheela. 2014. 'China is investing in Modi's ego', 15 September,

http://www.rediff.com/news/special/china-is-investing-in-modis-ego/20140915.htm (accessed on 16 September 2014).

Bhattacharya, Sanchita. 2014. 'Xinjiang An Important Determinant In Sino-Pakistan Relations – Analysis', 7 December, http://southasiamonitor.org/detail.php?type=sl&nid=9772 (accessed on 28 September 2015).

Embassy of India, Beijing, China. 'Economic and Trade Relations', http://www.indianembassy.org.cn/DynamicContent.aspx?MenuId=97&SubMenuId=0 (accessed on 29 September 2015).

George, Varghese K. and Yashwant Raj. 2013. 'Pakistan Epicentre of Terrorism: Tone Down Expectations from Talks: PM', September 27, http://www.hindustantimes.com/world-news/pak-epicenter-of-terrorism-tone-down-expectations-from-talks-pm/article1-1128042.aspx (accessed on 28 September 2015).

Ministry of Defence, Government of India. 2015. 'Annual Report 2014-2015', http://www.mod.nic.in/writereaddata/AR1415.pdf (accessed on 29 September 2015).

Ministry of External Affairs, Government of India. 2014. 'Joint Statement between the Republic of India and the People's Republic of China on Building a Closer Developmental Partnership', *Bilateral Documents*, 19 September, http://www.mea.gov.in/bilateral-documents.htm?dtl/24022/Joint+Statement+between+the+Republic+of+India+and+the+Peoples+Republic+of+China+on+Building+a+Closer+Developmental+Partnership (accessed on 29 September 2015).

Ministry of External Affairs, Government of India. 2015. 'Visit of Prime Minister to China (May 14-16, 2015)', http://www.mea.gov.in/outgoing-visit-info.htm?2/772/Visit+of+Prime+Minister+to+China+May+1416+2015 (accessed on 29 September 2015).

Press Trust of India (PTI). 2013. 'Can't Allow China to Dominate India, We Need to Take Ourselves Seriously: Modi', 19 October, http://archive.indianexpress.com/news/cant-allow-china-to-dominate-india-we-need-to-take-ourselves-seriously-modi/1184413/0 (accessed on 19th July 2015).

Rajan, D. S. 2014. 'The Meaning of Latest Chinese Transgression in Ladakh, Ahead of Chinese President's Visit to India', *SAAG*, Paper No. 5790, 18 September. http://www.southasiaanalysis.org/node/1617 (accessed on 29 September 2015).

Ward, Jonathan. 2014. 'Chinese Analysts Interpret Modi's New India', The Jamestown Foundation, *China Brief*, Vol. 14, Issue 12, June 19, 2014, pp. 6-9. http://www.jamestown.org/programs/chinabrief/single (accessed on 18 July 2014).

Ye Hailin. 2008. 'China and South Asian Relations in a New Perspective', http://www.eaber.org/sites/default/files/documents/IAPS_Hailin_2008.pdf (accessed on 25 September 2014).

The views expressed here are those of the author and not necessarily of the Institute of Chinese Studies.

The ICS is an interdisciplinary research institution which has a leadership role in promoting Chinese and East Asian Studies in India. The *ICS Analysis* aims to provide informed and balanced inputs in policy formulation based on extensive interactions among wide community of scholars, experts, diplomats and military personnel.

ICS ANALYSIS *BACK ISSUES*

No. 33 | Aug 2015	China's Role in Afghan-Taliban Peace Talks: Afghan Perspectives
No. 32 | Aug 2015	India's Myanmar Strike: The China Factor
No. 31 | July 2015	Deconstructing the Shanghai Stock Exchange Crash
No. 30 | May 2015	China and Vietnam: Neither Thick Friends nor Constant Antagonists
No. 29 | Mar 2015	Applying the 'Going Out' Strategy: Chinese Provinces and Cities Engage India
No. 28 | Mar 2015	China, the Debt Trap and the Future Prospects for its Economy
No. 27 | Feb 2015	Will he or Won't he? Recent Sino-Tibetan Exchanges over the Dalai Lama's Reincarnation
No. 26 | Jan 2015	China-Sri Lanka Ties Post-Rajapaksa: Major Changes Unlikely
No. 25 | Jan 2015	Chinese Combat Troops Join UN Peacekeeping Operations in South Sudan: A New Beginning?
No. 24 | Dec 2014	China's 'Going Out' Policy: Sub-National Economic Trajectories
No. 23 | Dec 2014	The Ebola Crisis: Responses from India and China
No. 22 | Nov 2014	18th CPC Central Committee Fourth Plenum: Rule of Law with Chinese Characteristics

Institute of Chinese Studies
ICS
中国研究所 DELHI

8/17, Sri Ram Road, Delhi - 110054, INDIA
Tel: +91-11-2393 8202 | Fax: +91-11-2383 0728
info@icsin.org | http://icsin.org
@ics_delhi | facebook.com/icsin.delhi